



थाली-चम्मच के शोर से गूंजा जंतर-मंतर, छात्रों के भविष्य को लेकर सरकार पर बरसे प्रदर्शनकारी

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर शनिवार को एक ऐसा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला जिसने न सिर्फ राहगीरों का ध्यान खींचा, बल्कि सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक नई बहस छेड़ दी। एक हाथ में थाली, दूसरे हाथ में चम्मच और जुवान पर लगातार गूंजता नारा—“भो धर्मेंद्र प्रधान गो”। दूर से देखने पर यह दृश्य कई लोगों को कोरोना काल की याद दिला रहा था, जब पूरे देश में लोगों से घरों की बालकनी और छतों पर खड़े होकर थाली और चम्मच बजाने की अपील की गई थी। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार निशाने पर कोरोना वायरस नहीं, बल्कि परीक्षा प्रणाली में कथित अनियमितताओं और छात्रों के भविष्य से जुड़े सवाल थे।

जंतर-मंतर पर जुटी भीड़ का नेतृत्व युवा संगठन कांक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) कर रही थी। संगठन के संस्थापक अभिजीत दीपके के आह्वान पर देश के विभिन्न हिस्सों से छात्र, प्रतियोगी परीक्षा अस्थायी और उनके समर्थक यहां पहुंचे थे। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि पिछले कुछ वर्षों में लगातार सामने आए पेपर लीक, परीक्षा में गड़बड़ियां, परिणामों में देरी और भर्ती प्रक्रियाओं में अनिश्चितता ने लाखों युवाओं के भविष्य को

संकट में डाल दिया है। उनका कहना था कि वर्षों की मेहनत और तैयारी के बावजूद छात्र बार-बार ऐसी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, जिन पर उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती, लेकिन नुकसान उन्हें ही उठाना पड़ता है। प्रदर्शन की सबसे खास बात उसका तरीका था। पारंपरिक नारों और भाषणों के बजाय प्रदर्शनकारियों ने थाली और चम्मच बजाकर अपना विरोध दर्ज कराया। जैसे ही अभिजीत दीपके मंच पर पहुंचे, पूरे इलाके में बर्तनों की आवाज गूंजने लगी। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यह प्रतीकात्मक विरोध है, जिसके माध्यम से वे सरकार का ध्यान छात्रों की समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। उनका तर्क था कि यदि कभी देश को एकजुट करने के लिए थाली-चम्मच का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो छात्रों की आवाज उठाने के लिए भी इसी तरीके को अपनाया जा सकता है।

जंतर-मंतर का पूरा इलाका घंटों तक नारों और बर्तनों की आवाज से गूंजता रहा। प्रदर्शनकारियों के हाथों में विभिन्न प्रकार की तख्तियां थीं, जिन पर परीक्षा प्रणाली में सुधार, पेपर लीक पर रोक और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग



लिखी गई थी। कई छात्र ऐसे भी थे जो वर्षों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और बार-बार होने वाली गड़बड़ियों से खुद को उगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनका कहना था कि जब कोई परीक्षा रह होती है

या उसका प्रश्नपत्र लीक हो जाता है, तो सिर्फ एक परीक्षा नहीं रुकती, बल्कि लाखों युवाओं के सपने और योजनाएं भी प्रभावित होती हैं। कांक्रोच जनता पार्टी के संस्थापक

अभिजीत दीपके ने प्रदर्शन के दौरान कहा कि यह आंदोलन किसी एक परीक्षा या एक भर्ती प्रक्रिया तक सीमित नहीं है। यह उन सभी छात्रों की आवाज है जो व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बार-बार सामने आने वाली घटनाओं के बावजूद जिम्मेदारी तय नहीं की जाती और न ही दोषियों को ऐसी सजा मिलती है जो भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोक सके। उनका कहना था कि जब तक परीक्षा प्रणाली पूरी तरह पारदर्शी और भरोसेमंद नहीं बनेगी, तब तक युवाओं का विश्वास बहाल नहीं हो पाएगा। इस प्रदर्शन से पहले अभिजीत दीपके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खुला पत्र भी लिखा था। पत्र में उन्होंने छात्रों की समस्याओं का उल्लेख करते हुए परीक्षा प्रबंधन और भर्ती प्रक्रियाओं में सुधार की मांग की थी। साथ ही उन्होंने उन मामलों में जवाबदेही तय करने की आवश्यकता पर जोर दिया था, जिनमें कथित रूप से परीक्षा संबंधी अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। सीजेपी लगातार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी उठा रही है और प्रदर्शन के दौरान यह मांग प्रमुख रूप से सुनाई दी।

जंतर-मंतर पर आयोजित यह प्रदर्शन संगठन का दूसरा बड़ा आंदोलन माना जा रहा है। इससे पहले भी सीजेपी ने परीक्षा प्रणाली से जुड़े मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। संगठन का दावा है कि लाखों छात्रों की समस्याओं को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जा रहा है और यही कारण है कि युवाओं में निराशा बढ़ रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सरकार को यह समझना होगा कि प्रतियोगी परीक्षाएं केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं हैं, बल्कि करोड़ों परिवारों की उम्मीदों और भविष्य से जुड़ा विषय हैं। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। जंतर-मंतर और उसके आसपास के इलाके में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। पुलिस लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए थी ताकि किसी प्रकार की अग्रिय घटना न हो। प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, लेकिन जैसे-जैसे भीड़ बढ़ती गई, सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता भी बढ़ती गई। शाम होते-होते प्रदर्शन के समय को लेकर नया विवाद सामने आ गया। अभिजीत दीपके ने दिल्ली पुलिस से प्रदर्शन की अवधि बढ़ाने की मांग की थी ताकि अधिक से अधिक छात्र अपनी बात रख सकें। हालांकि पुलिस ने निर्धारित समय के बाद

अनुमति बढ़ाने से इनकार कर दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच बातचीत का दौर चला। सीजेपी के नेताओं ने कहा कि छात्रों की समस्याएं इतनी गंभीर हैं कि उन्हें कुछ घंटों के प्रदर्शन तक सीमित नहीं किया जा सकता। पुलिस की ओर से अनुमति न बढ़ाए जाने के बावजूद अभिजीत दीपके ने स्पष्ट कहा कि वे प्रदर्शन स्थल को तुरंत छोड़ने के पक्ष में नहीं हैं। उनका कहना था कि जब तक छात्रों की आवाज को गंभीरता से नहीं सुना जाएगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इस बयान के बाद प्रदर्शन स्थल पर मौजूद समर्थकों ने और जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। कुछ समय के लिए माहौल और अधिक राजनीतिक हो गया तथा विभिन्न छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी अपनी-अपनी बातें रखीं। प्रदर्शन में शामिल छात्रों का कहना था कि उनका उद्देश्य किसी राजनीतिक दल का समर्थन या विरोध करना नहीं, बल्कि अपने भविष्य को सुरक्षित बनाना है। उनका आरोप था कि पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के कारण प्रतिभाशाली और मेहनती छात्रों को बार-बार नुकसान उठाना पड़ता है। कई छात्रों ने कहा कि वे वर्षों तक तैयारी करते

हैं, आर्थिक और मानसिक दबाव झेलते हैं, लेकिन जब परीक्षा रह होती है या विवादों में घिर जाती है तो उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता है। जंतर-मंतर पर हुआ यह प्रदर्शन एक बार फिर इस बात का संकेत देता है कि परीक्षा और भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर युवाओं में चिंता और असंतोष मौजूद है। चाहे विरोध का तरीका थाली और चम्मच बजाने जैसा प्रतीकात्मक क्यों न हो, लेकिन उसके पीछे छिपा संदेश गंभीर है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे केवल पारदर्शी, निष्पक्ष और विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली चाहते हैं, जहां किसी छात्र का भविष्य प्रशासनिक लापरवाही या कथित भ्रष्टाचार की भेंट न चड़े। अब देखना यह होगा कि इस विरोध प्रदर्शन का सरकार और संबंधित संस्थाओं पर कितना प्रभाव पड़ता है। फिलहाल जंतर-मंतर पर गूंजे थाली-चम्मच के शोर ने इतना जरूर साबित कर दिया है कि देश का युवा अपने भविष्य से जुड़े मुद्दों पर चुप बैठने को तैयार नहीं है। वह अपनी आवाज हर संभव तरीके से उठाना चाहता है और चाहता है कि उसकी मेहनत, उसके सपनों और उसके अधिकारों को गंभीरता से सुना जाए।

टीएमसी में मचा सियासी भूचाल, 440 करोड़ के फंड पर घमासान से खुलकर सामने आई अंदरूनी जंग

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की सियासत में एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस के भीतर का संघर्ष खुलकर सामने आ गया है। विधानसभा चुनाव में इटके झेलने के बाद पार्टी नहां राजनीतिक चुनौतियों से जुझ रही है, वहीं अब आर्थिक और संगठनात्मक विवादों ने भी नेतृत्व की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पार्टी के बैंक खातों में जमा सैकड़ों करोड़ रुपये के फंड को लेकर उठे विवाद ने टीएमसी के अंदर चल रही खींचतान को सार्वजनिक कर दिया है। इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में एक और बागी नेता ऋतब्रत बनर्जी के नाम हैं तो दूसरी ओर पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक कुणाल घोष, जिन्होंने अपने ही पूर्व सहयोगी पर तीखा हमला बोलते हुए कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। राजनीतिक गलियारों में सबसे अधिक चर्चा उस कथित 440 करोड़ रुपये के फंड को लेकर हो रही है, जो पार्टी के तीन प्रमुख बैंक खातों पर कार्रवाई की गई, जिससे इन खातों से धन निकासी पर रोक लग गई। इस घटनाक्रम ने पार्टी के भीतर कई तरह

के सवाल खड़े कर दिए हैं और नेतृत्व की कार्यशैली पर भी बहस तेज हो गई है। इसी बीच बेलेघाटा से विधायक और तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख चेहरों में शामिल कुणाल घोष ने बागी नेता ऋतब्रत बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। घोष ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि ऋतब्रत बनर्जी को पार्टी के फंड और उसके प्रबंधन पर इतना ही संदेह था, तो उन्हें चुनाव के दौरान उसी फंड का लाभ नहीं लेना चाहिए था। उन्होंने सवाल उठाया कि जिस व्यवस्था पर आज आरोप लगाए जा रहे हैं, उसी व्यवस्था के संसाधनों का उपयोग अतीत में क्यों किया गया। उनके अनुसार यह केवल राजनीतिक अवसरवाद है और ऐसे आरोपों के पीछे व्यक्तिगत नाराजगी अधिक दिखाई देती है। कुणाल घोष का बयान ऐसे समय आया है जब पार्टी के भीतर असंतोष की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। पिछले कुछ समय से टीएमसी के कई नेताओं और जनप्रतिनिधियों द्वारा संगठनात्मक फैसलों पर सवाल उठाए जाते रहे हैं। हालांकि पार्टी नेतृत्व लगातार यह दावा करता रहा है कि संगठन पूरी तरह एकजुट है, लेकिन हालिया घटनाक्रम ने इन दावों को चुनौती देने का काम किया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि किसी भी बड़े राजनीतिक दल में मतभेद होना सामान्य बात है, लेकिन जब विवाद सार्वजनिक मंचों तक पहुंच

जाए और आर्थिक मामलों से जुड़ जाए, तब उसका असर संगठन की छवि पर भी पड़ता है। इस पूरे विवाद की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी वे बैंक खाते हैं, जिनमें कथित तौर पर सैकड़ों करोड़ रुपये जमा बताए जा रहे हैं। इन खातों पर लगी रोक ने पार्टी के भीतर वित्तीय प्रबंधन को लेकर नई बहस शुरू कर दी है। सूत्रों का दावा है कि खातों में लगभग 440 करोड़ रुपये मौजूद हैं, जबकि कुछ रिपोर्टें में यह राशि 600 करोड़ रुपये तक बताई गई थी। हालांकि वास्तविक राशि को लेकर अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इतना स्पष्ट है कि मामला बेहद संवेदनशील और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बन चुका है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि किसी भी दल के लिए उसका संगठनात्मक फंड बेहद अहम होता है। चुनावी गतिविधियों से लेकर संगठन संचालन, जनसंपर्क अभियानों और विभिन्न कार्यक्रमों तक के लिए इसी धन का उपयोग किया जाता है। ऐसे में यदि किसी पार्टी के प्रमुख खातों पर रोक लग जाए तो उसका असर केवल आर्थिक नहीं, बल्कि राजनीतिक भी होता है। यही कारण है कि यह मामला पश्चिम बंगाल की राजनीति में चर्चा का प्रमुख विषय बन गया है।

विपक्षी दल भी इस मुद्दे को लेकर लगातार हमलावर हैं। उनका आरोप है कि टीएमसी के भीतर लंबे समय से चल रही असंगठित अव खुलकर सामने आ रही है। विपक्ष का कहना है कि यदि पार्टी के अपने ही नेता वित्तीय पारदर्शिता पर सवाल उठा रहे हैं, तो यह गंभीर चिंता का विषय है। हालांकि टीएमसी नेतृत्व इस पूरे मामले को आंतरिक विवाद बताते हुए इसे राजनीतिक रूप से बढ़ा-चढ़ाकर पेश किए जाने का आरोप लगा रहा है। दूसरी ओर, पार्टी समर्थकों का तर्क है कि किसी भी बड़े संगठन में विचारों का मतभेद हो सकता है, लेकिन इससे संगठन की मूल शक्ति प्रभावित नहीं होती। उनका कहना है कि तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बनी हुई है और कुछ नेताओं की नाराजगी से पार्टी की जनाधार पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर भी यह तथ्य नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि हाल के महिनो में पार्टी के भीतर असहमति के स्वर पहले की तुलना में लिए इसी धन का उपयोग किया जा रहा है। ऐसे में यदि किसी पार्टी के प्रमुख खातों पर रोक लग जाए तो उसका असर केवल आर्थिक नहीं, बल्कि राजनीतिक भी होता है। यही कारण है कि यह मामला पश्चिम बंगाल की राजनीति में चर्चा का प्रमुख विषय बन गया है।

टीएमसी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने प्रभावी ढंग से नहीं उठाया, जिससे देश के सम्मान और भारतीय नागरिकों के हितों की अनदेखी हुई है। सी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान हुई प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की द्विपक्षीय बैठक अब राजनीतिक विवाद का विषय बन गई है। अंतरराष्ट्रीय मंच पर दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत और उसके बाद सामने आए दृश्य तथा बयानों को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि जब भारतीय नागरिकों के जीवन और राष्ट्रीय सम्मान से जुड़ा मुद्दा मौजूद था, तब सरकार को अधिक दृढ़ और स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए था। कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने इस विषय पर आयोजित प्रस वार्ता में प्रधानमंत्री की विदेश नीति और



मुद्दे पर अपेक्षित दृढ़ता नहीं दिखाई गई और अमेरिकी पक्ष से किसी प्रकार की सार्वजनिक संवेदना या खेद व्यक्त नहीं किया गया। भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और सम्मान किसी भी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उनका आरोप था कि प्रधानमंत्री ने बैठक में इस मुद्दे को उस गंभीरता से नहीं उठाया जिसकी वे देशवासियों को थी। उन्होंने कहा कि सरकार बार-बार “राष्ट्र प्रथम” की बात करती है, लेकिन व्यवहार में उसकी प्राथमिकताएं कुछ और दिखाई देती हैं। प्रधानमंत्री से देश एक आत्मविश्वासपूर्ण और मजबूत नेतृत्व की अपेक्षा करता है, लेकिन बैठक की तस्वीरों और वीडियो से वैसा संदेश नहीं गया। कांग्रेस नेता ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में शिष्टाचार और कूटनीतिक भाषा का महत्व होता है, लेकिन इसके साथ ही राष्ट्रिय हितों की रक्षा करना भी उतना ही आवश्यक होता है। उनके अनुसार जब तीन भारतीय नाविकों की मौत जैसी घटना सामने थी, तब भारत को स्पष्ट रूप से अपनी चिंता और आपत्ति दर्ज करानी चाहिए थी। कांग्रेस का आरोप है कि इस

के अनुरूप नहीं थे। उन्होंने इसे भारत की वैश्विक छवि से जुड़ा विषय बताते हुए कहा कि दुनिया भारत को एक उपरती हुई महाशक्ति के रूप में देखती है और ऐसे में देश के नेतृत्व को भी उसी आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखनी चाहिए। कांग्रेस ने इस पूरे घटनाक्रम को विदेश नीति और राष्ट्रीय सम्मान के व्यापक प्रश्न से जोड़ने की कोशिश की है। पार्टी का कहना है कि भारत अब केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि वैश्विक मंच पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला देश है। इसलिए जब भारतीय नागरिकों को नुकसान पहुंचाने वाली कोई घटना होती है, तो उस पर स्पष्ट और कड़ा रुख अपनाना आवश्यक है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने इस अवसर का उपयोग भारतीय हितों की रक्षा करने के बजाय अपनी छवि को मजबूत करने के लिए किया। पवन खेड़ा ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर को लेकर भी टिप्पणी की और कहा कि सरकार के शीर्ष नेतृत्व को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिक प्रभावशाली और परिणामोन्मुखी कूटनीति अपनाने की आवश्यकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपनी उपलब्धियों का प्रचार करने में तो सक्रिय रहती है, लेकिन जब कठिन सवाल पूछने या जवाब मांगने की जरूरत होती है, तब वह उतनी मुखर नहीं दिखाई देती।

आय घटी तो मचा सियासी बवाल, अब बोले कालगे- जनसेवा को कभी नुकसान नहीं बताया

लातूर। राजनीति में दिए गए एक बयान को लेकर उठे विवाद के बीच कांग्रेस सांसद डॉ. शिवाजी कालगे ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि उनके शब्दों को संदर्भ से काटकर पेश किया गया और इससे एक ऐसा संदेश प्रसारित हुआ जो उनके वास्तविक विचारों से बिल्कुल मेल नहीं खाता। उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने कभी भी सार्वजनिक जीवन में आने को नुकसान नहीं बताया और न ही सांसद बनने पर किसी प्रकार का पछतावा व्यक्त किया है। उनके अनुसार वह केवल अपने पेशेवर जीवन पर पूरे प्रभाव का उल्लेख कर रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने उसे इस तरह प्रस्तुत किया मानो वह जननीति में आने को आर्थिक दृष्टि से घाटे का सौदा मानते हों। पिछले कुछ दिनों से डॉ. शिवाजी कालगे का एक बयान राजनीतिक और सोशल मीडिया हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ था। उनके द्वारा अपनी मंडिकल प्रैक्टिस और आय में आई कमी का जिक्र किए जाने के बाद विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं सामने आई थीं। कुछ लोगों ने इसे जनप्रतिनिधियों के जीवन में आने वाले बदलावों की ईमानदार स्वीकारोक्ति माना, जबकि कुछ ने इसे राजनीति में आने के बाद हुए आर्थिक नुकसान की शिकायत के रूप में प्रस्तुत किया। विवाद बढ़ने के बाद अब स्वयं सांसद को सामने आकर समझाई देनी पड़ी है। लातूर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे डॉ. शिवाजी कालगे ने सोशल मीडिया के माध्यम से जारी अपने स्पष्टीकरण में कहा कि एक साक्षात्कार के दौरान उनसे पूछा गया था कि सक्रिय राजनीति में आने के बाद उनकी निजी और पेशेवर जिंदगी पर क्या असर पड़ा है। उन्होंने उसी प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया था कि सांसद बनने के बाद उनकी चिकित्सा सेवाओं और अस्पताल के कार्यों को पहले की



कई लोगों ने यह सवाल उठाया कि क्या सांसद बनने के बाद उन्हें आर्थिक नुकसान हुआ है। इसी चर्चा ने धीरे-धीरे विवाद का रूप ले लिया। हालांकि अपने तजा बयान में कालगे ने स्पष्ट किया कि आय में कमी का जिक्र केवल एक तथ्यात्मक जानकारी थी, जिसका उद्देश्य यह बताना था कि अब उनका अधिक समय जनसेवा और राजनीतिक जिम्मेदारियों में व्यतीत हो रहा है। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपने पेशेवर जीवन का बड़ा हिस्सा समाज और जनता के लिए समर्पित करता है, तो उसके निजी व्यवसाय पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि वह उस जिम्मेदारी को बोझ मानता है। कांग्रेस सांसद ने इस अवसर पर जनप्रतिनिधि के रूप में अपनी भूमिका को लेकर भी विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि लोकसभा में जनता की आवाज उठाने और क्षेत्र के विकास के लिए काम करने का अवसर उनके लिए किसी भी आर्थिक लाभ से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि धन और आय की तुलना जनसेवा के अवसर से नहीं की जा सकती। उनके अनुसार लोगों का विश्वास जीतना और संसद तक पहुंचना उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। डॉ. कालगे ने अपनी राजनीतिक यात्रा का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि उनकी कोई निजी वार्षिक आयकर का भुगतान किया था, जबकि 2024-25 में उनकी आय कम होने के कारण उनका कर भुगतान घटकर लगभग 8.75 लाख रुपये रह गया। इस टिप्पणी के बाद राजनीतिक हलकों में बहस शुरू हो गई थी।

लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया। उन्होंने कहा कि पार्टी द्वारा दिखाया गया विश्वास और लातूर की जनता द्वारा दिया गया समर्थन उनके लिए सम्मान की बात है। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतकर सांसद पहुंचना उनके लिए केवल एक राजनीतिक उपलब्धि नहीं, बल्कि लोगों की अपेक्षाओं और विश्वास का प्रतीक है। यही कारण है कि वह अपनी जिम्मेदारियों को पूरी गंभीरता और निष्ठा के साथ निभाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके अनुसार कहना था कि यदि किसी जनप्रतिनिधि को अपने क्षेत्र की समस्याओं को समझना और उनका समाधान निकालना है, तो उसे स्वाभाविक रूप से अपने निजी कार्यों से कुछ समय निकालकर जनता के बीच रहना होगा। कालगे ने यह भी कहा कि राजनीति में आने के बाद उन्हें जो प्यार, सम्मान और समर्थन मिला है, उसकी कोई आर्थिक कीमत नहीं लगाई जा सकती। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यक्रमों, गठबंधन सहयोगियों और क्षेत्र की जनता ने जिस प्रकार उन पर भरोसा जताया है, वह उनके लिए किसी भी व्यक्तिगत लाभ से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यही विश्वास उन्हें लगातार काम करने और जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए प्रेरित करता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहने वाले कई पेशेवर लोगों को इसी प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर, वकील, उद्योगपति या अन्य पेशेवर जब राजनीति में उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि उनकी कोई निजी आय और पेशेवर गतिविधियों पर असर पड़ना असामान्य नहीं होता। लेकिन ऐसे मामलों में दिए गए बयानों की राजनीतिक व्याख्या भी तेजी से होने लगी है, जिससे कई बार मूल संदेश में पीछे छूट जाता है।

गरवी गुजरात हिन्दी

Jio Air Fiber

Jio Tv +

Jio Fiber

Daily Hunt

ebaba Tv

Dish Plus

DTH live OTT

Rock TV

Airtel

Amezone Fire

Roku Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार प्राप्त करने के लिए आज ही गरवी गुजरात हिंदी चैनल देखिये



संपादकीय

सेहत पर भारी विकास

इस बात में दो राय नहीं कि हरियाणा की समृद्धि में औद्योगिक विकास की बड़ी भूमिका रही है। जिसमें बड़ी संख्या में राज्य के लोगों को रोजगार भी मिला है। हरियाणा अपनी औद्योगिक सफलता की प्रेरक कहानी पर गर्व करता रहा है। मानेसर के ऑटोमोबाइल हब से लेकर राज्य भर में फैले मैयूफैक्टरिंग क्लस्टर के उद्योगों में बड़े पैमाने पर नौकरियों के अवसर पैदा हुए हैं। निस्संदेह, इससे राज्य के आर्थिक विकास को भी गति मिली है। लेकिन इस विकास की दूसरी तस्वीर चिंता बढ़ाने वाली है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की यह बात चिंतित करने वाली है कि राज्य में तीन हजार औद्योगिक इकाइयों में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले पर्याप्त उपकरण ही नहीं लगे हैं। जो एक गंभीर स्थिति को दर्शाती है। निस्संदेह, कोई भी विकास साफ हवा की कीमत पर नहीं किया जाना चाहिए। चिंता की बात यह भी है कि प्रदूषण नियामक उपकरणों की कमी वाली औद्योगिक इकाइयों की सूची में मानेसर सबसे ऊपर पाया गया है। यह औद्योगिक टाउनशिप न केवल हरियाणा का प्रमुख आर्थिक इंजन है, बल्कि हजारों श्रमिकों और उनके परिवारों का घर भी है। जो आज हर दिन कारखानों से निकलने वाले धुएं से प्रभावित हवा में सांस लेने को अभिशप्त हैं। विडंबना यह है कि अब तक इस संकट को गंभीरता से नहीं लिया गया। इस स्थिति को सुधारने के लिये कोई सार्थक पहल भी नहीं हुई है। बड़ी विचित्र बात है कि गाहे-बगाहे हर साल मौसमी स्मॉग या पराली जलाने को लेकर आरोप-प्रत्यारोपों का सिलसिला चलता रहता है। जबकि कोई वैज्ञानिक अध्ययन भी हमारे सामने नहीं आया कि स्मॉग व पराली जलाने की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में होने वाले प्रदूषण में कितनी भूमिका होती है। लेकिन जिन औद्योगिक इकायों से निकलने वाले प्रदूषण को हम नाप कर नियंत्रित कर सकते हैं, उस दिशा में कोई सार्थक पहल नहीं की गई। सालभर चलने वाली औद्योगिक उत्सर्जन की समस्या को प्राथमिकता के आधार पर संबोधित किया जाना चाहिए।

यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि वर्ष पर्यंत होने वाले औद्योगिक उत्सर्जन से हवा की गुणवत्ता खराब हो जाती है। जिससे सांस संबंधी रोगों को बढ़ावा मिलता है। ये स्थितियां लोगों के जीवन की गुणवत्ता में गिरावट ही पैदा करती हैं। विडंबना यह है कि पर्यावरण की दृष्टि से बेहद संवेदनशील इलाकों, विशेष रूप से देश के नेशनल कैपिटल रिजन यानी एनसीआर में काम करने वाली औद्योगिक इकाइयों को अपनी जिम्मेदारी व जवाबदेही का अच्छे से पता होता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसके बावजूद हजारों इकाइयों लक्ष्यों को ताक पर रखकर मुनाफा कमजाने में लगी हैं, वह भी हजारों लोगों की सांसों की कीमत पर। यह नियामक तंत्र द्वारा नियमों को लागू करने और जवाबदेही तय करने में बड़ी नाकामी को ही दर्शाता है। इस जटिल समस्या का समाधान सिर्फ नोटिस जारी करने तक सीमित नहीं होना चाहिए। वह बात अलग है कि कुछ छोटी और मध्यम दर्जे की कंपनियों को साफ-सुथरी टेक्नोलॉजी अपनाने के लिये तकनीकी सहायता और आर्थिक मदद की जरूरत हो सकती है। इसके बावजूद प्रदूषणरोधी उपकरण लगाने की समस्या-सीमा और निर्धारित मानकों को लेकर किसी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता। सही मायने में चेतावनी के बावजूद बार-बार नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ा जुर्माना लगाया जाना चाहिए। यह एक हकीकत है कि साफ हवा ओद्योगिक विकास में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करती है। यही स्थायी व दूरगामी परिणामों वाले विकास की अपरिहार्य शर्त भी है। सही मायनों में हरियाणा की अर्थव्यवस्था तब तक फल-फूल नहीं सकती, जब तक यहां के लोगों को अपनी सेहत की कीमत पर यह विकास करना पड़े। इसमें दो राय नहीं कि प्रगति और विकास की दृष्टि से राज्य के उद्योगों ने अग्रणी भूमिका निभाई है। इन उद्यमियों ने इन्वोवेशन और प्रतिस्पर्धा की कसौटी पर अपनी बेहतर क्षमताओं को साबित किया भी है। अब उन्हें इस बात के लिये प्रेरित करना होगा कि वे अब पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी निभाने में भी वैसी ही प्रतिबद्धता दर्शाएं। सही मायने में किसी भी समाज में असली समृद्धि तभी आ सकती है जब हमारी प्राथमिकताओं में जन-स्वास्थ्य पहले हो।

अभियान

तीन रातों का मौन, चौथे दिन का चमत्कार: जब पूरी दुनिया की नजरें टिक जाती हैं कामाख्या धाम पर

भारत की आध्यात्मिक परंपराएं जितनी प्राचीन हैं, उतनी ही रहस्यमयी भी हैं। यहां ऐसे अनेक तीर्थस्थल हैं जिनकी मान्यताएं केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे जीवन, प्रकृति और ब्रह्मंड के गहरे रहस्यों को भी अपने भीतर समेटे हुए हैं। इन्होंने अद्भुत स्थलों में एक नया सबसे अलग और विशिष्ट है—मां कामाख्या का पवित्र धाम। असम की राखीनी पहाड़ियों में नीलाचल पर्वत पर स्थित यह मंदिर एक एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि शक्ति, सृजन और प्रकृति के शाश्वत संबंध का जीवंत प्रतीक माना जाता है। वर्ष भर यहां श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा रहता है, लेकिन जून का महीना आते ही यह स्थान पूरी दुनिया के आध्यात्मिक मानचित्र पर विशेष महत्व प्राप्त कर लेता है। इसका कारण है अंबुबाची मेला, जिसे भारत के सबसे रहस्यमय और अनूठे धार्मिक आयोजनों में गिना जाता है।

जब देश के अधिकांश मंदिरों में विशेष पर्वों पर पूजा-पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों की संख्या बढ़ जाती है, तब कामाख्या मंदिर में ऐसा इक्के विपरीत होता है। यहां तीन दिनों के लिए मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। न आती होती है, न पढ़ाते होते हैं और न ही कोई नियमित पूजा संपन्न होती है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही इसके पीछे ऐसी धार्मिक मान्यता जुड़ी हुई है जिससे कामाख्या धाम को समस्त शक्तिपीठों में सबसे अलग पहचान दी है।

पौराणिक कथाओं के अनुसार जब राजा दश ने

योग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह केवल रोगों से मुक्ति नहीं देता, बल्कि जीवन को दिशा देता है। पातंजलि ने योग को “चित्तवृत्ति निरोध” कहा है। अर्थात् मन की चंचलता और विकारों पर नियंत्रण। जब मन नियंत्रित होता है, तब व्यक्ति में निर्णय क्षमता, धैर्य और आत्मविश्वास का विकास होता है।

प्रेरणा

एकाग्रता का चमत्कार: सफलता की हर ऊँचाई तक पहुँचने का अमोघ मंत्र

मनुष्य के जीवन में अनेक शक्तियाँ छिपी होती हैं, लेकिन उन सभी शक्तियों को सही दिशा देने वाली सबसे महत्वपूर्ण शक्ति एकाग्रता है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को केंद्रित करना सीख लिया, उसके लिए कठिन से कठिन लक्ष्य भी आसान हो जाते हैं। इतिहास गवाह है कि संसार के अधिकांश महान व्यक्तियों ने अपनी सफलता का श्रेय किसी न किसी रूप में एकाग्रता को ही दिया है। चाहे यह विज्ञान का क्षेत्र हो, साहित्य हो, कला हो, खेल हो या आध्यात्मिकता, हर क्षेत्र में वही लोग आगे बढ़े हैं जिन्होंने अपने मन को भटकने से रोककर अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखा। एक दिन की बात है। नन्ही एन. वेल्लारमथी अपनी कक्षा में अन्य बच्चों के साथ बैठी थीं। उस दिन शिक्षिका बच्चों को महान संन्यासी और विचारक स्वामी विवेकानंद के जीवन के बारे में पढ़ा रही थीं। पूरी कक्षा बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन रही थी। शिक्षिका ने बच्चों से कहा, “स्वामी विवेकानंद का मानना था कि यदि उन्हें अपनी शिक्षा फिर से आरंभ करने का अवसर मिले, तो वे केवल तथ्यों और जानकारीयों को इकट्ठा करने पर ध्यान नहीं देंगे, बल्कि सबसे पहले अपनी एकाग्रता की शक्ति को विकसित करेंगे। उनका विश्वास था कि एकाग्र मन अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी प्राप्त कर सकता है।”

एक दिन के मन में यह बात सुनकर उत्सुकता जाग उठी। शिक्षिका ने आगे कहा, “स्वामी विवेकानंद एकाग्रता का तुलना सूर्य की किरणों से करते थे। क्या तुम समझे सूर्य को देखा है?” सभी बच्चों ने उत्साहपूर्वक शिर हिलाकर उत्तर दिया। सूर्य तो वे प्रतिदिन देखते थे, लेकिन उसकी किरणों और एकाग्रता के बीच क्या संबंध हो सकता है, यह जानने के लिए वे उत्सुक हो उठे। शिक्षिका बच्चों को केवल शब्दों में समझाना नहीं चाहती थीं। वे एक छोटी-सा प्रयोग करने का निश्चय किया। उन्होंने एक लंबा लता और उसके नीचे एक कागज रखा। फिर सूर्य की किरणों को उस लेंस के माध्यम से एक बिंदु पर केंद्रित किया। कुछ ही क्षणों में बच्चों ने आश्चर्य से देखा कि कागज से धुँआँ उठने लगा और फिर वह जल गया। यह दृश्य देखकर पूरी कक्षा रोमांचित हो उठी। नन्ही वेल्लारमथी की आँखों में आश्चर्य चमक उठा। वह उत्साहित होकर बोली, “वाह ! यह तो चमत्कार है।” शिक्षिका मुसकुराई और बोलीं, “नहीं बच्चों, यह कोई चमत्कार नहीं है। यह एकाग्र ऊर्जा का परिणाम है। सूर्य की किरणें पूरे आकाश में फैली रहती हैं, इसलिए उनका प्रभाव समान्य होता है। लेकिन जब वही किरणें एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती हैं, तो उनमें इतनी शक्ति आ जाती है कि वे कागज को भी जला सकती हैं। ठीक इसी प्रकार मनुष्य का मन भी होता है। यदि उसका ध्यान इधर-उधर भटकता रहे, तो उसकी शक्ति बिखर जाती है। लेकिन जब वह अपने लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित हो जाता है, तो असंभव दिखाई देने वाले कार्य भी संभव हो जाते हैं।” शिक्षिका की यह बात वेल्लारमथी के मन में गहराई से उतर गई। उस दिन उन्होंने केवल एक प्रयोग नहीं देखा था, बल्कि जीवन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत समझा था। तुलना सूर्य की किरणों से करते थे। क्या तुम समझे सूर्य को देखा है?” सभी बच्चों ने उत्साहपूर्वक शिर हिलाकर उत्तर दिया। सूर्य तो वे प्रतिदिन देखते थे, लेकिन उसकी किरणों और एकाग्रता के बीच क्या संबंध हो सकता है,

आज जब पूरी दुनिया युद्धों, आतंकवाद, हिंसा, मानसिक तनाव, पर्यावरणीय संकट और नई-नई बीमारियों की चुनौतियों से घिरी हुई है, तब मानवता एक ऐसे मार्ग की तलाश में है जो केवल शरीर को ही नहीं, बल्कि मन, बुद्धि और आत्मा को भी संतुलित कर सके। ऐसे संक्रमणकाल में योग केवल एक व्यायाम पद्धति या स्वास्थ्य विज्ञान नहीं, बल्कि मानव सभ्यता के लिए आशा का प्रकाश-स्तंभ बनकर उभरा है। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज केवल भारत का नहीं, बल्कि सम्पूर्ण विश्व का उत्सव बन गया है। भारत अनादिकाल से योग की भूमि रहा है। इस भूमि के कण-कण में ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों और योगियों की साधना की सुगंध समाई हुई है। वैदिक ऋषियों से लेकर भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, आदि शंकराचार्य, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द, महात्मा गांधी, श्री अरविन्द, आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ तक, सभी ने योग को जीवन के उत्कर्ष और मानव कल्याण का आधार माना। योग ने भारत की आध्यात्मिक चेतना को ही नहीं गढ़ा, बल्कि विश्व को यह संदेश भी दिया कि मनुष्य का वास्तविक विकास भीतर से प्रारंभ होता है। आज विश्व जिस दिशा में बढ़ रहा है, वह चिंता का विषय है। रूस-यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया में संघर्ष, आतंकवाद की घटनाएँ, साम्प्रदायिक तनाव और हथियारों की बढ़ती होड़ मानव सभ्यता को भय और असुरक्षा की ओर धकेल रही है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, विज्ञान और तकनीक ने अभूतपूर्व सुविधाएँ दी हैं, लेकिन इनके साथ विनाश की संभावनाएं भी बढ़ी हैं। ऐसे समय में योग की प्रासंगिकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। योग मनुष्य को भीतर से शांत, संतुलित और संवेदनशील बनाता है। जब व्यक्ति के भीतर शांति होगी, तभी समाज और राष्ट्र में शांति का वातावरण निर्मित होगा। योग का मूल अर्थ ही है-जुड़ना। यह मनुष्य को मनुष्य से, आत्मा को परमात्मा से, व्यक्ति को समाज से और मानवता को सम्पूर्ण सृष्टि से जोड़ता है। योग विज्ञान नहीं, एकांत का दर्शन है। इसलिए वह हिंसा, युगल, आतंक और संघर्ष का स्वाभाविक प्रतिकरोधक है। जो व्यक्ति योग



के माध्यम से अपने भीतर करुणा, प्रेम और अहिंसा का विकास करता है, वह किसी के प्रति द्वेष नहीं रख सकता। यही कारण है कि महात्मा गांधी की अहिंसा और भगवान महावीर का जीव-दाया का संदेश भी योग की व्यापक चेतना से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज मानसिक तनाव, अवसाद, अनिद्रा, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग, मोटापा और जीवनशैली से जुड़ी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। आधुनिक जीवन की भागदौड़ में मनुष्य बाहरी उपलब्धियों के पीछे दौड़ रहा है, लेकिन भीतर से खाली और अशांत होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में योग एक समग्र चिकित्सा-पद्धति के रूप में सामने आया है। योग शरीर, मन और भावनाओं के बीच संतुलन स्थापित करता है। नियमित आसन, प्राणायाम और ध्यान व्यक्ति की प्रतिरक्षा शक्ति को बढ़ाते हैं, तनाव को कम करते हैं तथा मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाते हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान भी दुनिया ने अनुभव किया कि स्वस्थ जीवनशैली और मजबूत प्रतिरोधक क्षमता कितनी महत्वपूर्ण है। उस समय योग, प्राणायाम और ध्यान ने करोड़ों लोगों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज भी चिकित्सक और स्वास्थ्य विशेषज्ञ स्वीकार करते हैं

कि योग अनेक बीमारियों की रोकथाम और प्रबंधन में अत्यंत प्रभावी सहायक माध्यम है। यह दवाओं का विकल्प नहीं, बल्कि स्वस्थ जीवन का आधार है। योग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह केवल रोगों से मुक्ति नहीं देता, बल्कि जीवन को दिशा देता है। पातंजलि ने योग को “चित्तवृत्ति निरोध” कहा है। अर्थात् मन की चंचलता और विकारों पर नियंत्रण। जब मन नियंत्रित होता है, तब व्यक्ति में निर्णय क्षमता, धैर्य और आत्मविश्वास का विकास होता है। आज की पीढ़ी, जो तनाव, प्रतिस्पर्धा और डिजिटल व्यसनों के बीच जी रही है, उसके लिए योग मानसिक संतुलन का सबसे सशक्त माध्यम बन सकता है। योग का एक महत्वपूर्ण पक्ष उसका नैतिक और मानवीय आयाम भी है। यम और नियम जैसे सिद्धांत सत्य, अहिंसा, अहिंसा, अहिंसा, अहिंसा और संतोष की शिक्षा देते हैं। यदि इन मूल्यों को व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में अपनया जाए, तो हिंसा, भ्रष्टाचार, अपराध और सामाजिक विद्वेष जैसी समस्याओं में स्वाभाविक सुलुन का अवसर बने। विद्यालय, विश्वविद्यालयों, कार्यालयों, उद्योगों और सामाजिक संस्थाओं में योग को जीवनशैली के रूप में अपनाने को पहल हो। परिवारों में योग, ध्यान और सकरात्मक संवाद की संस्कृति विकसित हो। यदि व्यक्ति स्वस्थ होगा तो

महासभा द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया जाना भारत की सांस्कृतिक शक्ति और विश्वसनीयता का बड़ा प्रमाण है। आज दुनिया के लगभग सभी देशों में योग का अभ्यास किया जा रहा है। यह केवल एक कूटनीतिक उपलब्धि नहीं, बल्कि भारतीय ज्ञान परंपरा की वैश्विक विजय है। प्रधानमंत्री मोदी ने योग के साथ-साथ भारतीय अहिंसा, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, मिलेट्स आधारित भारतीय खानपान और “वसुधैव कुटुम्बकम्” को अवधारणा को भी विश्व मंच पर स्थापित करने का प्रयास किया है। यह संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है कि भारत केवल आर्थिक या सैन्य शक्ति बनने का सपना नहीं देखता, बल्कि मानवता को स्वस्थ, संतुलित और शांतिपूर्ण जीवन का मार्ग दिखाने की क्षमता भी रखता है। यही “विश्वगुरु भारत” की अवधारणा का मूल है। भारतीय आयुर्वेद और योग का संबंध भी अत्यंत गहरा है। आयुर्वेद शरीर की चिकित्सा करता है, जबकि योग मन और चेतना को संतुलित करता है। दोनों मिलकर स्वस्थ जीवन की संपूर्ण व्यवस्था प्रस्तुत करते हैं। आज जब दुनिया रासायनिक दवाओं के दुष्प्रभावों और जीवनशैली जनित रोगों से चिंतित है, तब योग और आयुर्वेद एक वैकल्पिक नहीं, बल्कि पूरक एवं स्थायी समाधान के रूप में उभर रहे हैं। इतिहास साक्षी है कि योग ने हर युग में एक मौन क्रांति को जन्म दिया है। इसने राजाओं को ऋषि बनाया, योद्धाओं को संत बनाया और सामान्य मनुष्यों को असाधारण व्यक्तिव प्रदान किए। स्वामी विवेकानन्द ने योग के माध्यम से भारतीय अध्यात्म को विश्व के सामने रखा। महात्मा गांधी ने कर्मयोग और अहिंसा के बल पर एक साम्प्रदाय को चुनौती दी। श्री अरविन्द ने योग को मानव चेतना के विकास का साधन बनाया। यह सब योग की परिवर्तनकारी शक्ति के उदाहरण हैं। इसलिए योग दिवस उत्सव का नहीं, संकल्प का अवसर बने। विद्यालय, विश्वविद्यालयों, कार्यालयों, उद्योगों और सामाजिक संस्थाओं में योग को जीवनशैली के रूप में अपनाने को पहल हो। परिवारों में योग, ध्यान और सकरात्मक संवाद की संस्कृति विकसित हो। यदि व्यक्ति स्वस्थ होगा तो

चीन-अमेरिका नहीं भारत बना रहा पेरिस से भी 5 गुना बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, क्या है अडानी का दुनिया हिलाने वाला मेगा प्लान?

30 जुलाई 2012 की दोपहर 2 बजकर 35 मिनट पर भारत के नॉर्थन ग्रिड पर अचानक लोड बढ़ा। ग्रिड इस दबाव को झेल नहीं पाया और देखते ही देखते ईस्टर्न और नॉर्थ-ईस्टर्न ग्रिड भी ताश के पत्तों की तरह ढह गए। परिणाम यह हुआ कि देश के 22 राज्यों की बिजली गुल हो गई। अस्पतालों के ऑपरेशन थिएटर बंद होने लगे, वॉटेलेंटर जन्तरेड बैकअप पर आ गए और झुलसाती गर्मी में करोड़ों मोटर पसीने से तर-बतर हो गए। इस ब्लैकआउट का सबसे डरावना पहलू था पश्चिम बंगाल और झारखंड के कोल-बेल्ट (Coal Belts) में हुआ हादसा। जैसे ही बिजली काफ़ी, खदानों के लिफ्ट और पनू एक नया ऊर्जा परिस्थितिकी तंत्र तैयार हो रहा है। इस प्रोजेक्ट का आकार हेराक़र कर देने वाला है। यह 72,600 हेक्टेयर यानी लगभग 726 वर्ग किमी की बंजर और खाली जमीन पर फैला है। इसका मतलब है कि यह पेरिस शहर से भी बड़ा है। जब यह पूरी क्षमता पर काम करेगा तो हर साल लगभग 81 बिलियन किलोवाट घंटा साफ बिजली पैदा करेगा। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझो तो यह बिजली इतनी ज्यादा है कि चिली या नीदरलैंड जैसे स्ट्रीट (रोड पर बाजार) में भागदड़ मच गईं। इसके मार्केट 2% से ज्यादा नीचे आ चुका था। नियमों के मुताबिक, यदि बाजार 10% तक गिर जाता, तो लोअर सर्किट लग जाता और उस दिन के लिए ट्रेडिंग पूरी तरह बंद कर दी पड़ती। यह सोचना गलत होगा कि पावर ग्रिड या एनर्जी क्राइसिस सिर्फ विकासशील देशों की समस्या है। साल 2022 में दुनिया ने इसका सबसे बड़ा सबूत देखा। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ते ही जैसे ही जर्मनी की गैस और पावर सप्लाई बाधित हुई, वहां की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। यूरोप की सबसे मजबूत आर्थिक महाशक्ति कहे जाने वाले जर्मनी में एक ही साल के भीतर करीब 24,000 कंपनियों को खुद को दिवालिया कि घोषित करना पड़ा। 2012 का भारतीय क्राइसिस हमें एक ही सबक सिखा रहा है। आधुनिक दुनिया में युद्ध टैकों या मिसाइलों से नहीं, बल्कि किसी देश की पावर ग्रिड को उप निकास करने की क्षमता है। ऊर्जा सुरक्षा ही असल में किसी देश की सबसे बड़ी संप्रभुता है। जर्मनी G7 का इकलौता देश बन गया जहां पर दो रिसर्सेस पैरा। जबकि जर्मनी के पास लिए एयर कंडीशन कंॉलिंगो बसाई गई हैं। रियल हाउसिंग सेक्टर है। असल में बस एक अकाउंटिंग सिस्टम है। असली करेसी एनर्जी होती है जो रियल ट्रॉंसमिशन लाती है। भारत भी इस बात को धील भाँति समझ चुका है और भारत के गुजरात में स्थित कच्छ का विशाल रण, एक ऐसा क्षेत्र जिसे कभी बंजर और अनुपयोगी माना जाता था। आज दुनिया के सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के निवेश, हजारों मेगावाट क्षमता, विशाल सोलर पार्क, पवन ऊर्जा संयंत्र, बंदी स्टोरेज सिस्टम और रणनीतिक महत्व के कारण खावड़ा प्रोजेक्ट पूरी दुनिया का ध्यान अपनी

डांग जिला समग्र देश में द्विन-पिट शौचालय के मामले में देश का मॉडल बना

►पूर्णतः आदिवासी जनसंख्या वाला डांग जिला ग्रामीण स्वच्छता तथा फीकल स्लज मैनेजमेंट में देश को दिखा रहा है नई राह

►डांग जिले में 95 प्रतिशत परिवारों ने ट्विन-पिट शौचालय अपनाए

►प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2014 में खुले में शौचमुक्त का लक्ष्य प्राप्त करने तथा गाँवों में ठोस व तरल कूड़ा प्रबंधन में सुधार लाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की शुरुआत की थी

अयोध्या के राम मंदिर के दान में हुई लूट के मुद्दे पर AAP प्रदेश प्रवक्ता हिमांशु ठक्कर का बयान

► किसानों के खेत, छात्रों के पेपर के बाद अब मंदिर का दान भी सुरक्षित नहीं है: हिमांशु ठक्कर AAP

► अयोध्या में लूट चल रही है, तब अंग्रेजों को भी शर्म आए ऐसा कृत्य सत्ताधारी पार्टी के लोग कर रहे हैं: हिमांशु ठक्कर AAP

► सोने-चांदी की लगभग 1200 ईंटें गायब हो गई थीं, करोड़ों की लूट की रकम की चर्चा हो रही है: हिमांशु ठक्कर AAP

► मंदिर में काम करने वाले लोगों के पास एक समय साइकिल भी नहीं थी, अब दस गाड़ियां आ गई हैं: हिमांशु ठक्कर AAP

► जिन लोगों के पास फूटी कौड़ी नहीं थी, उनके पास अब करोड़ों की जमीनें कहां से आ गई?: हिमांशु ठक्कर AAP

► दान लूटने वालों को पता है कि ऊपर तक के लोगों का आशीर्वाद उनके साथ है: हिमांशु ठक्कर AAP

► पिछले आठ महीनों के CCTV फुटेज डिलीट कर दिए गए: हिमांशु ठक्कर AAP

अहमदाबाद/गुजरात: आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हिमांशु ठक्कर ने वीडियो के माध्यम से कहा कि आज तो वित्तीय खाते सुरक्षित नहीं हैं, छात्रों के पेपर सुरक्षित नहीं हैं और मंदिरों में आने वाला दान भी सुरक्षित नहीं है। पिछले एक सप्ताह से सोशल मीडिया, न्यूज चैनलों और कुछ रामभक्त धर्माचार्यों तथा संतों द्वारा जो समाचार सामने आ रहे हैं, उन्हें देखकर वास्तव में हमारा हृदय द्रवित हो उठता है। "सोने-चांदी की लगभग 1200 ईंटें गायब हो गई थीं, करोड़ों की लूट की रकम की चर्चा हो रही है। जब सोमनाथ का ताला टूटा था तब मुगल थे और जब अनेक विद्यापीठों, छोटे-बड़े मंदिरों और तीर्थस्थलों को नुकसान पहुंचाया गया था तब अंग्रेज थे। लेकिन आज जब अयोध्या में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, तब मुगल या अंग्रेज नहीं बल्कि सत्ताधारी पार्टी से जुड़े लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। यह कोई छोटी घटना नहीं है। करोड़ों रामभक्तों का हृदय वास्तव में द्रवित हो उठता है। जो लोग भगवान श्रीराम के प्रति आस्था, समर्पण भाव और भक्ति भाव से हजारों किलोमीटर की यात्रा करके दर्शन के लिए पहुंचते हैं और अपनी

गंधीनगर, 20 जून : गुजरात के डांग जिले के आदिवासियों ने शायद स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत ट्विन-पिट शौचालयों को लोकप्रिय बनाने वाले अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर के विज्ञापन नहीं देखे होंगे, लेकिन उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को इतनी प्रभावी ढंग से अपनाया है कि आज डांग जिला ग्रामीण स्वच्छता के क्षेत्र में देश के लिए एक मॉडल बना है।

घने जंगलों, हरियाले पहाड़ों और वर्षा ऋतु के आह्लादक दृश्यों के लिए विख्यात डांग जिला आज स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत फीकल स्लज मैनेजमेंट के महत्वपूर्ण घटक ट्विन-पिट शौचालयों के व्यापक स्वीकार के लिए भी पहचान प्राप्त कर रहा है।

जिला ग्रामीण विकास अधिकरण (डीआरडीए)-डांग के समन्वयक श्री विपुल परदेशी ने कहा, "डांग जिले में तीन तहसीलों और 310 गाँव हैं। डांग जिले

अयोध्या के राम मंदिर के दान में हुई लूट के मुद्दे पर AAP प्रदेश प्रवक्ता हिमांशु ठक्कर का बयान

बात तो यह है कि ऐसे समाचार भी सामने आए हैं कि पिछले आठ महीनों के CCTV फुटेज डिलीट या डिस्टर्ब कर दिए गए हैं। AAP प्रवक्ता हिमांशु ठक्कर ने आगे कहा कि इतनी बड़ी घटना में CCTV की पूरी रिकॉर्डिंग गायब हो जाए, तो क्या किसी के सहयोग के बिना यह संभव है? कुछ समय तक यह मुद्दा चर्चा में रहेगा, फिर धीरे-धीरे सब शांत हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा दुख तो रामभक्तों की भावनाओं के साथ हुआ खिलवाड़ है। हाल ही में ऐसे समाचार भी आए हैं कि दान में उल्लेखनीय कमी आई है। लेकिन सवाल यह है कि सच्चा दान क्या है? दान की पवित्रता कैसे बनाए रखी जा सकती है? शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में करोड़ों रुपये का दान उपयोग किया जाए तो उसका लाभ समाज को मिलता है। किसी गरीब बच्चे की स्कूल या कॉलेज की फीस भर दी जाए, किसी जरूरतमंद को उपचार मिल जाए, तो शायद भगवान श्रीराम अधिक प्रसन्न होंगे। मैं सभी रामभक्तों से अनुरोध करता हूँ कि इस देश की संस्कृति हमारी संस्कृति है। यदि मंदिरों में आने वाला दान भी सुरक्षित न रहे, तो लोगों की आस्था पर असर पड़ता है। मंदिरों में बढ़ते VIP कल्चर और ऐसी घटनाओं पर सामूहिक रूप से विचार करने की आवश्यकता है। सरकार के पास अपने संसाधनों की सुरक्षा करने की भी क्षमता नहीं है। कई बार सरकारी तंत्र की लापरवाही के मामले सामने आते हैं। तो फिर मंदिरों के प्रबंधन में सरकार की भूमिका कितनी और कैसी होनी चाहिए, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। इस देश में अनेक मठ, पीठ, संत और शंकराचार्य परंपराएं हैं। क्या सनातन परंपरा के अग्रणियों के साथ बैठकर ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती कि मंदिरों में एक निश्चित राशि से अधिक आय होने पर उसका एक हिस्सा शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय विकास के लिए उपयोग किया जाए? समय आ गया है कि हम इन मुद्दों पर गंभीरता से विचार करें। भगवान श्रीराम सभी को सद्बुद्धि दें। "वसुधैव कुटुम्बकम्" और "विद्या धनं सर्वधनं प्रधानम्" जैसे हमारी संस्कृति के मूल्यों को फिर से जीवंत करने की आवश्यकता है। आज स्थिति ऐसी बन गई है कि लोग मंदिरों के दान पर भी सवाल उठाने लगे हैं। इस दुर्भाग्यपूर्ण मानसिकता और परिस्थिति पर निश्चित रूप से विचार करना होगा।

डॉल्फिन संरक्षण में गुजरात का योगदान महत्वपूर्ण

राज्य के समुद्र तटीय क्षेत्र में लगभग 680 से अधिक डॉल्फिन की उपस्थिति : वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री अर्जुन मोढवाडिया

गांधीनगर : वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री अर्जुन मोढवाडिया ने कहा है कि वन्यजीवों के साथ-साथ सबसे सुंदर एवं आकर्षक जलचर जीव 'डॉल्फिन' के संरक्षण-संवर्धन में गुजरात ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में जलचर एवं वन्यजीव संरक्षण तथा संवर्धन के विशेष प्रयासों के परिणामस्वरूप वर्ष 2025 की अंतिम गणना के अनुसार गुजरात के 4,087 वर्ग किलोमीटर में फैले समुद्री क्षेत्र में लगभग 680 से अधिक डॉल्फिन दर्ज हुई हैं। वहीं जलचर एवं वन्यजीव पर्यटन क्षेत्र में भी गुजरात ने लंबी छलांग लगाई है। गुजरात के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों शिवराजपुर तथा पोशित्रा का समुद्र तट डॉल्फिन के लिए 'केट स्पॉट' के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पानी बहुत ही स्वच्छ होने के कारण डॉल्फिन सरलता से दिखाई दे जाती हैं।

श्री मोढवाडिया ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संघे मार्गदर्शन में गुजरात में वन विभाग ने पिछले 12 वर्षों में समुद्र तट पर मैंग्रोव के साथ-साथ जलचर जीवों के संरक्षण तथा उनके आवास-विकास के लिए अनेक प्रकार के संयुक्त प्रयास शुरू किए हैं। कच्छ की खाड़ी के दक्षिणी भाग में स्थित मरीन नेशनल पार्क तथा मरीन सैंकचुरी के ओखा से नवलखी तक फैले 1,384 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सर्वाधिक 498 डॉल्फिन होने की संभावना है, जबकि कच्छ की खाड़ी के उत्तरी भाग में कच्छ वृत्त अंतर्गत 1,821 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 168, भावनगर के 494 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 10 तथा मोरेखी के 388 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 4 डॉल्फिन देखी गई हैं। इस



प्रकार: कच्छ की खाड़ी में स्थित भारत का यह प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान डॉल्फिन का मुख्य घर है।

उन्होंने कहा, "स्वस्थ इकोसिस्टम के लिए डॉल्फिन बहुत ही महत्वपूर्ण जलचर प्राणी है। समुद्री स्तनधारी प्राणियों के कुछ शीर्ष शिकारी खाद्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और समुद्री इकोसिस्टम में संतुलन सुनिश्चित करने में भी सहायता करते हैं। इन डॉल्फिनों को बचाने में कच्छ से भावनगर तक समुद्र में मछली पकड़ने का कार्य करने वाले मछुआरे भाइयों का योगदान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इन सर्वग्राही प्रयासों के परिणामस्वरूप गुजरात के समुद्र तट पर दिखाई देने वाली डॉल्फिन देश-विदेश के पर्यटकों के लिए नया आकर्षण केन्द्र बनीं हैं।" उन्होंने जोड़ा कि डॉल्फिन लुप्तप्राय प्रजातियों में शामिल होने के कारण उनका शिकार करना या उन्हें नुकसान पहुंचाना गैर-जमानती अपराध है।

गुजरात में दिखाई देने वाली डॉल्फिन की विशेषताएँ

गुजरात के समुद्री क्षेत्र में मुख्यतः इंडो-पैसिफिक हम्पबैक डॉल्फिन तथा बॉटलनोज डॉल्फिन, इन दो प्रकार की डॉल्फिन सबसे अधिक दिखाई देती



मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक परिवार को शौचालय उपलब्ध कराने की ओर गाँवों में ठोस तथा तरल कूड़ा प्रबंधन में सुधार लाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की शुरुआत की थी। उनके नेतृत्व में यह पहल स्वच्छता, महिलाओं की सुरक्षा और स्वर्गांगीण ग्रामीण स्वास्थ्य पर केन्द्रित एक व्यापक जन जागरण तथा व्यवहार परिवर्तन अभियान में विकसित हुई है।

राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों के जिलों के साथ एक वचुआल संवाद आयोजित किया था। इस बैठक की अध्यक्षता केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी. आर. पाटिल ने की थी। इस बैठक के दौरान विभिन्न राज्यों ने नवीन तथा व्यापक स्तर पर लागू किए जा सकने वाले स्वच्छता मॉडल प्रस्तुत किए थे। बैठक में सुदूरवर्ती आदिवासी क्षेत्रों में ट्विन-पिट शौचालयों को बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए गुजरात के डांग जिले को विशेष उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया था।

श्री पाटिल ने भाग लेने वाले राज्यों की प्रशंसा करते हुए कहा था, "ऐसे स्वच्छता मॉडल केवल स्वच्छ भारत के विजन को साकार करने में ही सहायक नहीं बनते, अपितु टिकाऊ कूड़ा प्रबंधन के माध्यम से रोजगार के अवसर भी सृजित करते हैं।" ट्विन-पिट शौचालय मानव मल को सुरक्षित रूप से विघटित कर पोषक

तत्वों से भरपूर जैविक खाद में परिवर्तित करता है। ग्रामीण स्वच्छता ढाँचे को मजबूत बनाने के साथ यह टेक्नोलॉजी भूमिगत जल प्रदूषण तथा असुरक्षित कूड़ा निस्तारण के जोखिम को कम करके सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की भी रक्षा करती है।

ट्विन-पिट शौचालय कैसे काम करता है ?

ट्विन-पिट शौचालय सामान्य शौचालय की तरह ही कार्य करता है, लेकिन इसकी विशेषता यह है कि यह मानव मल को सुरक्षित जैविक खाद में परिवर्तित करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा भी इस टेक्नोलॉजी को प्रभावी तथा टिकाऊ स्वच्छता समाधान के रूप में मान्यता दी गई है।

सीवर व्यवस्था तथा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जुड़े परंपरागत शौचालयों की तुलना में ट्विन-पिट शौचालय घर के स्तर पर

ही कूड़े का प्रबंधन करता है। मानव मल पहले गड्ढे में जाता है, जहाँ उसका प्राकृतिक रूप से विघटन होता है। पहला गड्ढा भर जाने के बाद मल प्रवाह को दूसरे गड्ढे में मोड़ दिया जाता है। तब तक पहले गड्ढे में मौजूद मल पूरी तरह विघटित होकर सुरक्षित और पोषक तत्वों से भरपूर खाद में परिवर्तित हो जाता है, जिसे सरलता से बाहर निकालकर खाद के रूप में उपयोग में लिया जा सकता है।

इस प्रकार के शौचालय महंगी सीवर व्यवस्था की आवश्यकता को समाप्त करते हैं और भूमि एवं जल स्रोतों को प्रदूषित किए बिना कचरे का सुरक्षित प्रबंधन करते हैं।

सस्ती और टिकाऊ टेक्नोलॉजी

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के निर्माण के लिए सरकार 12,000 रुपये की सहायता प्रदान करती है और स्थल पर ही कूड़ा

प्रबंधन के लिए ट्विन-पिट टेक्नोलॉजी को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करती है। ट्विन-पिट शौचालय लागत की दृष्टि से सस्ते हैं और इनमें परंपरागत फ्लश शौचालयों की तुलना में कम पानी की जरूरत पड़ती है। इसलिए ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अत्यंत अनुकूल होते हैं।

इस प्रणाली में सामान्यतः लगभग तीन फीट गहराई वाले दो गोलाकार गड्ढे आस-पास बनाए जाते हैं। गड्ढों की दीवारें मधुमक्खी के छत्ते (हनीकॉम्ब पैटर्न) के आकार की बनाई जाती हैं, जिससे तरल पदार्थ आसपास की मिट्टी में आसानी से शोषित हो सके, जबकि गड्ढे के तल में कोई लाईनिंग नहीं की जाती है। सामान्यतः सीमेंट मोर्टार से युक्त ईंटों का उपयोग किया जाता है, परंतु स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पत्थर, लकड़ी के खंभे, कंक्रीट रिंग, पकी हुई मिट्टी या पुनः उपयोग किए गए ड्रमों का भी उपयोग हो सकता है।



गुजरात सरकार



Yoga for Healthy Ageing

12वाँ अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026

21 जून 2026 | रविवार
सुबह 6:00 बजे से 8:00 बजे तक

स्थान:- सेठ एल.एच. साइंस कॉलेज, मानसा



गरिमामय उपस्थिति

श्री भूपेन्द्रभाई पटेल

माननीय मुख्यमंत्री, गुजरात

विशेष उपस्थिति

श्री हर्ष संघवी

माननीय उपमुख्यमंत्री, गुजरात



"12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर, आइए योग को अपनी जीवनशैली बनाएँ और हर उम्र में स्वस्थ, सक्रिय तथा ऊर्जावान रहें।"

- हर्ष संघवी
उपमुख्यमंत्री, गुजरात

